सिंचित क्षेत्र विकास का उद्धेश्य इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। इस संगठन ने वर्ष 1974 में कार्य करना प्रारंभ किया , जिसका मुख्य कारण राजस्थान राज्य के उत्तर-पश्चिमी भाग में निर्माणाधीन इंदिरा गांधी नहर परियोजना में उपलब्ध पानी , जो हिमाचल प्रदेश/पंजाब की व्यास व सतलुज नदी के राजस्थान को आवंटित हिस्से के अंतर्गत प्राप्त हो रहा था , का अधिकतम उपयोग कृषि कार्यों में करने का रहा है। इस संगठन ने न सिर्फ राष्ट्रीय उत्पादकता में अपना योगदान दिया बल्कि उत्तर-पश्चिमी राजस्थान की विस्तृत भू-भाग वाले क्षेत्र के विकास , जिसमें प्रत्येक काश्तकार के खेत तक पक्के खाले का निर्माण , स्वच्छ जल हेतु डिग्गियों का निर्माण , विभिन्न चक/गांवों को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण , नहर/सड़क/खेतों की सुरक्षा हेतु वनीकरण , चारागाह विकास , मछली उत्पादन , कृषि अनुसंधान एवं विस्तार , काश्तकारों के आवास के लिए चक आबादी , काश्तकारों की फसल के विक्रय के उचित मूल्य के लिए कम से कम दूरी पर मंडियों का विकास तथा कुछ क्षेत्र में होने वाले जल प्लावन पर प्रभावी नियंत्रण जैसे दुरूह व जन उपयोगी कार्यों में योगदान दिया।

राजस्थान के इस विस्तृत थार डेजर्ट जिसमें प्राकृतिक नदियों का दूर-दूर तक नामोनिशान नहीं था व जिसमें शिफ्टिग रेतीले टिलों का भारी वर्चस्व था। शुष्क वातावरण वाले क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा व अति गहराई वाले भू-जल स्तर ने स्थानीय निवासियों के जीवने को दूभर कर रखा था , जिसके फलस्वरूप उनको निकटवर्ती अन्य राज्यों की ओर खाद्यान्न , पशुओं के चारे व पीने के पानी के लिए पलायन करने के लिए विवश होना पड़ता था।

19 वीं सदी के प्रारंभ में यह तथ्य बीकानेर राज्य के तत्कालीन प्रशासक महाराजा श्री गंगासिंह जी ने आत्मसात करते हुए सीमित संसाधान/धन से श्रीगंगानगर जिले के बड़े भू-भाग के लिए पंजाब से पानी लेकर बीकानेर कैनाल (जिसे गंग कैनाल का नाम भी दिया गया है) का सफलतापूर्वक निर्माण करवाया। इसी से प्रेरित होकर महाराजा श्री गंगासिंह जी ने अपने राज्य के तत्कालीन मुख्य अभियंता (सिंचाई) , श्री कंवरसेन के माध्यम से थार रेगिस्तान के इस भू-भाग के लिए राजस्थान नहर (वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर) , जिसका उद्गम व्यास व सतलुज नदी के सन्धि स्थल हरिके बैराज (जिला फिरोजपुर पंजाब) से करना प्रस्तावित कर प्रारंभिक कार्य करवाना प्रारंभ किया।

कालान्तर में स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के सहयोग से विश्व की अधिकतम लम्बाई की मानव निर्मित्त नहर निर्माण का दुरूह व कठिन कार्य वर्ष 1958 में तत्कालीन गृहमंत्री (भारत सरकार) श्री गोविन्द बल्लभ पंत के कर कमलो से प्रारंभ हुआ , जिसमें वर्तमान में 850 किमी. से भी अधिक लम्बाई में बहाव द्वारा पानी प्रवाह हो रहा है तथा 19.63 लाख हैक्टेयर क्षेत्र (लिफ्ट सिंचाई सहित) के विशाल भू भाग में सिंचाई प्रस्तावित/हो रही है। राजस्थान नहर परियोजना के प्रथम वोल्यूम जो वर्ष 1958 में प्रकाशित हुआ के अनुसार यह नहर कच्ची बनाई जानी ही प्रस्तावित थी , जिसे कालान्तर में पक्की बनाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त इसी वोल्यूम के अनुसार इस नहर में प्रारंभ में नेवीगेशन का प्रावधान भी रखा गया था , जिससे जलपोत/नोका संचालन के द्वारा व्यापार व आवागमन के साधन का विकास किया जाना प्रस्तावित था , परन्तु कालान्तर में इस व्यवस्था को ड्रोप कर दिया गया।

किसी भी सिंचाई परियोजना का मुख्य उद्देश्य , उपलब्ध पानी का समुचित उपयोग कर अधिकतम क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाकर कृषि उत्पादन व अन्य लाभ प्राप्त कर राष्ट्र को समृद्धिशाली बनाना होता है।

प्रारंभ में काश्तकार के खेतों को जलापूर्ति कच्चे खालों के माध्यम से होती थी , जिसमें अंतिम छोर पर पूर्ति न केवल बाधित रहती बल्कि सीमित व बहुमूल्य जल का अनावश्यक ह्रास होता था। इस समस्या के निराकरण हेतु पक्के खालों के निर्माण का निर्णय लिया गया , जिससे तकनीकी आधार पर अधिकतम क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रारंभ से अंतिम छोर तक समान रूप से साप्ताहिक बाराबंदी पद्धति से सिंचित योग्य भूमि के अनुपात में जलापूर्ति की जा सके।

परियोजना का लोकेशन मैप निम्न प्रकार है -

Location of the Project

इन कठिन परिस्थितियों के माध्यम से मिलने वाले पानी की एक-एक बूंद के अधिकतम उपयोग के लिए ही सिंचित क्षेत्र विकास संगठन का सृजन किया गया। प्रारंभ में इस संगठन को इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण के लिए स्वीकृत किया गया परन्तु कालान्तर में वर्ष 1988 में द्वितीय चरण के लिए , वर्ष 2004-05 में सिद्धमुख नोहर सिंचाई प्रणाली के लिए तथा वर्ष 2005-06 में अमरसिंह सब ब्रांच सिंचाई प्रणाली के लिए स्वीकृति दी गई।

विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं , इंदिरा गांधी नहर प्रथम चरण , द्वितीय चरण , सिद्धमुख नोहर व अमरसिंह सब ब्रांच प्रणाली का संक्षिप्त नक्शा निम्नानुसार है -

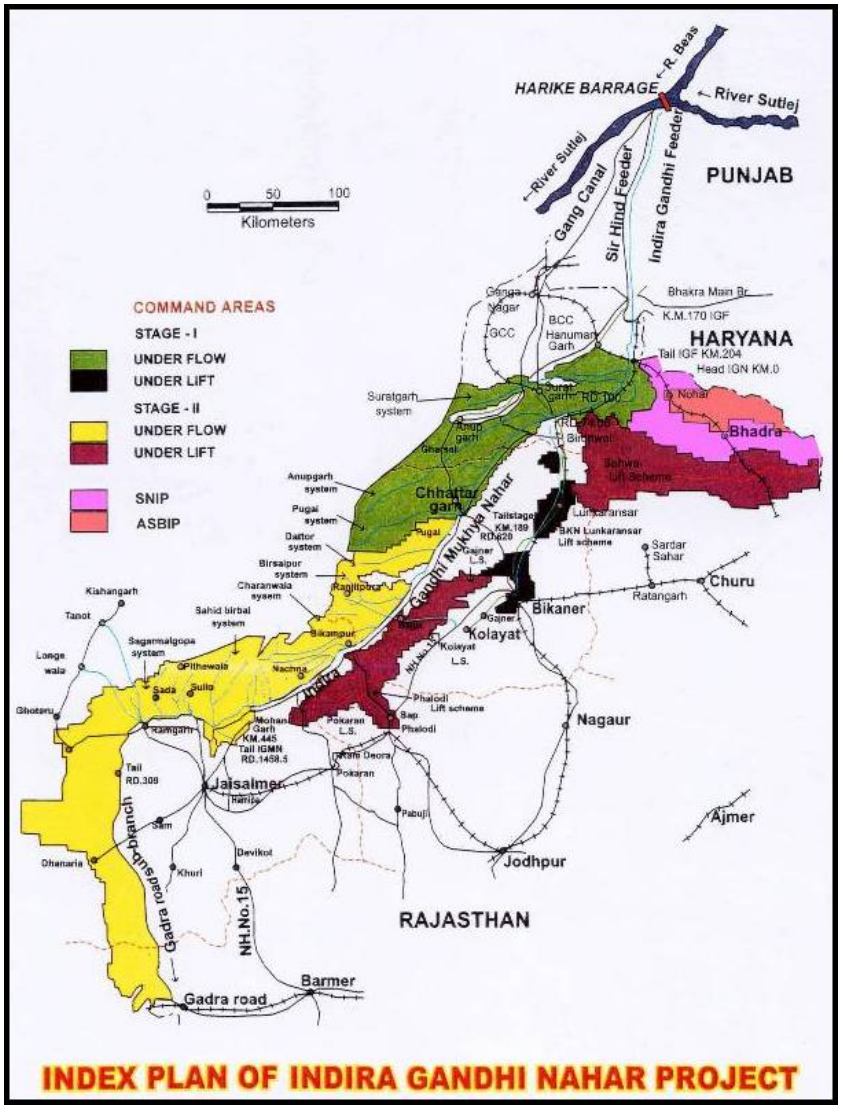

परियोजना के मुख्य मुख्य प्रभाव निम्न प्रकार परिलक्षित हुए है -

- परियोजना क्षेत्र में रेगिस्तान को फैलने से रोकना संभव हो पाया।
- क्षेत्र के लोगो का जीवन स्तर कृषि उत्पादन वार्षिक 17.30 लाख मैट्रिक टन होने व 1700 करोड़ रूपये की आय प्रतिवर्ष होने से ऊंचा हुआ है।
- परियोजना क्षेत्र में पानी की उपलब्धता के कारण अन्य क्षेत्र के लोगो का इस क्षेत्र में बसने के प्रति रूझान बढ़ा। परियोजना क्षेत्र में वर्ष 1961 में 26.26 लाख की आबादी थी जो सिंचित क्षेत्र बढ़ने से वर्ष

2001 में 80.00 लाख हो गई जो कि तीन गुना से भी अधिक है। राज्य में सामान्य आबादी वृद्धि 20 से 24 प्रतिशत दर्ज की गई है जबकि सिंचित क्षेत्र में यही दी 35 से 40 प्रतिशत रही है।

- पशुधन की बढोत्तरी हुई है। वर्ष 1961 में परियोजना क्षेत्र में पशुधन गाय , भैंस , भेड़ , बकरी व ऊँट की संख्या 10.50 लाख आँकी गई जो कि सिंचित क्षेत्र विकसित होने से बढ़कर वर्ष 2001 में लगभग 42.45 लाख हो गई है जो कि चार गुना से भी अधिक है।
- परियोजना क्षेत्र में उद्योग धन्धों का विकास हुआ। परियोजना से पूर्व इस क्षेत्र में केवल ऊन व कपड़े से संबंधित कुछ उद्योग स्थापित थे। पानी की उपलब्धता से कृषि उत्पादन बढ़ा एवं क्षेत्र में उद्योगों की बहुतायत में वृद्धि हुई। क्षेत्र में मिनरल्स व पशु धन से प्राप्त उत्पादनों जैसे ऊन , दूध तथा पशुखाल व हड्डिये से संबंधित उद्योग व मूंगफली उत्पादन से गोडू , बज्जू , बीकानेर व लूनकरणसर क्षेत्रों में तेल उद्योगों का भारी विस्तार हुआ। वर्ष 1975-76 व 1978-79 के मध्य 175 नये उद्योग परियोजना क्षेत्रों में स्थापित किये गये।
- वनो का विकास संभव हो सका है।
- रोजगार में बढोत्तरी हुई , परियोजना क्षेत्रों में उद्योगो एवं अन्य साधनों के विस्तार से करीब 6 लाख लोगो को स्थायी रोजगार मिला , तथा आगामी तीन वर्षो में 1.50 लाख लोगों को ओर रोजगार मिलने की संभावना है।
- परियोजना सिंचित क्षेत्र के विकास के साथ आँधियों में रेतीली हवाओं की कमी के कारण टिड्डी दलों के बाहर से होने वाले आक्रमण में कमी आई है।
- पक्के खाले बनने के कारण अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है जिसके कारण कृषि जिन्सों के उत्पादन में बढोत्तरी हुई है।
- परियोजना क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ है।
- परियोजना क्षेत्र में सड़को का विकास आवागमन के साधनों में बढोत्तरी डिग्गियों के निर्माण से पीने के पानी का उपलब्ध होना , नहरों के साथ वनों का विकास , चरागाहों का विकास , मत्स्य पालन , आबादी विकास , कृषि मंडियों का विकास एवं वाटर लोगिंग की समस्या का समाधान हुआ है।